28-03-2022

निर्यात तत्परता सूचकांक 2021

समाचार पत्रों मे क्यों ?

नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI), 2021 के अनुसार, गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है।

सूचकांक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, क्योंकि उच्च औद्योगिक गतिविधियों के साथ समुद्र तटीय बंदरगाहों वाले राज्य भारत के अधिकांश निर्यात के लिये ज़िम्मेदार हैं।

त्वरित मुद्दा ?

- चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा निर्यात के लिये एक सुविधाजनक नियामक ढाँचे को प्रोत्साहित करना।
- सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उप स्तंभ और 60 संकेतक शामिल हैं तथा इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
- ईपीआई उप-राष्ट्रीय स्तर (राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों) पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डेटा-संचालन का प्रयास है।
- यह प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए विभिन्न योगदानों की जाँच कर भारत की निर्यात क्षमता पर प्रकाश डालता है।

अन्य प्रमुख तथ्य ?

ग्यारह उप-स्तंभ

- सूचकांक में 11 उप-स्तंभों- निर्यात प्रोत्साहन नीतिः संस्थागत ढाँचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, वित्त तक पहुँच, निर्यात बुनियादी ढाँचा, व्यापार समर्थन अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना निर्यात विविधीकरण और विकास अभिविन्यास के आधार पर श्रेणी तैयार की गई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ?

- सूचकांक के पीछे निहित विचार इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करने हेतु एक बेंचमार्क निर्मित करना है ताकि उन्हें इस क्षेत्र में एक अनुकूल निर्यात वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।
- निर्यात में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में सहांयकरू सूचकांक नीति निर्माताओं और निर्यातकों को गति प्रदान करने, बाधाओं की पहचान करने तथा राज्य हेतु एक व्यवहार्य निर्यात की रणनीति बनाने और इसकी जाँच करने हेतु एक आवश्यक उपकरण है।
- राज्य सरकार के लिये पथ-प्रदर्शक – सूचकांक राज्य सरकारों के लिये निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में क्षेत्रीय प्रदर्शन को चिह्नित करने हेतु एक सहायक मार्गदर्शिका होगी और इस प्रकार निर्यात में सुधार एवं वृद्धि करने के बारे में महत्त्वपूर्ण नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
- राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा – इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों ('तटीय', 'लैंडलॉक्ड', 'हिमालयी' और 'यूटी/सिटी-स्टेट्स') के बीच अनुकूल निर्यात-संवर्द्धन नीतियों को लागू कर प्रतिस्पर्द्धा

को बढ़ाना, नियमों को आसान बनाना, उप-राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने व निर्यात के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण तथा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार हेतु रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करना है।

- EPI भारत के निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों के लिये तीन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है –
  1) निर्यात बुनियादी ढाँचे में भिन्नता और अंतर-क्षेत्रीय विभिद्ता।
  2) राज्यों में कमज़ोर व्यापार समर्थन और विकास अभिविन्यास।
  3) महत्त्वपूर्ण निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढाँचे की कमी।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन की जाँच – इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन एवं निर्यात हेतु तैयारी की जाँच करना है।

अन्य प्रमुख तथ्य ?

चार स्तंभ

- नीति – निर्यात और आयात के लिये रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति।
- बिज़नेस इकोसिस्टम – एक कुशल बिज़नेस इकोसिस्टम जो राज्यों को निवेश आकर्षित करने और स्टार्ट-अप शुरू करने हेतु व्यक्तियों के लिये एक सक्षम बुनियादी ढाँचा बनाने में मदद करता है।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र – कारोबारी माहौल का आकलन करना, जो निर्यात के लिये विशिष्ट हो।
- निर्यात प्रदर्शन – यह एकमात्र आउटपुट-आधारित पैरामीटर है जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्यात गतिविधियों की जाँच करता है।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

प्रश्न – निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिए –

1. नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI), 2021 के अनुसार, गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है।
2. सूचकांक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, क्योंकि उच्च औद्योगिक गतिविधियों के साथ समुद्र तटीय बंदरगाहों वाले राज्य भारत के अधिकांश निर्यात के लिये ज़िम्मेदार हैं।
3. सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उप स्तंभ और 60 संकेतक शामिल हैं तथा इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।

उपरोक्त मे से कौन-से/सा कथन सत्य है –

(A) 01 और 02 (B) 02 और 03
(C) 01 और 03 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर – (D) उपरोक्त सभी

COP-4 मीनामाता सम्मेलन

समाचार पत्रों मे क्यों ?

पार्टियों के सम्मेलन (COP–4) में पारा पर मिनामाता सम्मेलन (Minamata Convention on Mercury) में भाग लेने वाले हितधारकों ने पारा वाले उत्पादों की सूची का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है जिसे चरणबद्ध करने की योजना बनाई गई है।

त्वरित मुद्दा ?

- पारा पर COP–4 मिनामाता सम्मेलन 21 से 25 मार्च, 2022 तक इंडोनेशिया के बाली में हुआ।
- यह सम्मेलन पहले ऑनलाइन खंड के समापन के बाद फिर से शुरू हुआ जो नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था।
- COP–4 सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि कन्वेंशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए रूपरेखा। इस अधिवेशन में नौ निर्णय लिए गए।
- इसमें राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने के खनन (ASGM), तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, पारा अपशिष्ट सीमा और पारा को छोड़ने का कार्यान्वयन शामिल है।
- सभी परियोजनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों के तहत जेंडर को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- साथ ही इस बैठक के दौरान बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बल मिला।
- जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, और अपशिष्ट और प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने का भी निर्णय लिया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ?

- इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे को जारी करने और मानवजनित उत्सर्जन से बचाना है।
- इस सम्मेलन में, पारा युक्त उत्पादों जैसे कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, पेपर, फोटोग्राफ फिल्म और उपग्रहों के लिए प्रणोदक को चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया गया था।
- बाली घोषणा (Bali Declaration) – मेजबान राष्ट्र द्वारा "Bali Declaration on Combatting Global Illegal Trade of Mercury" भी प्रस्तुत की गई।
- गैर–बाध्यकारी प्रकृति की इस राजनीतिक घोषणा का उद्देश्य अवैध पारा व्यापार का मुकाबला करने के लिए व्यावहारिक उपकरण विकसित करना और सूचनाओं, प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

प्रश्न – निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिए –

1. COP–4 सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि कन्वेंशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए रूपरेखा। इस अधिवेशन में नौ निर्णय लिए गए।
2. इसमें राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने के खनन (ASGM), तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, पारा अपशिष्ट सीमा और पारा को छोड़ने का कार्यान्वयन शामिल है।
3. सभी परियोजनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों के तहत जेंडर को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

उपरोक्त मे से कौन–से/सा कथन सत्य है –

(A) 01 और 02 (B) 02 और 03

(C) 01 और 03 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर – (D) उपरोक्त सभी